13 मई 1952 को आयोजित हुआ था राज्यसभा का पहला सत्र। जुलाई 2018 से नियमों में बदलाव के बाद से राज्यसभा सदस्य सदन में 22 भारतीय भाषाओं में भाषण दे सकते हैं क्योंकि ऊपरी सदन में सभी 22 भारतीय भाषाओं में एक साथ व्याख्या की सुविधा है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 24 जनवरी 2020

राज्यों में कितनी जरूरी द्विसदनीय व्यवस्था

आंध्रप्रदेश विधानसभा में सत्ताधारी वाइएसआर कांग्रेस ने तीन राजधानियां बनाने के प्रस्ताव को प्रचंड बहुमत (175 में से 151 सीटें) के चलते निम्न सदन से पारित तो करा लिया लेकिन इसे विधान परिषद (विधान मंडल का उच्च सदन) ने अस्थायी रूप से रोक दिया है। विधानसभा में जहां जगनमोहन रेड्डी सरकार बहुमत में हैं। वहीं विधान परिषद में मुख्य विपक्षी पार्टी तेलगुदेशम के पास 58 में से 28 सीटें हैं। माना जा रहा है कि अब राज्य सरकार उच्च सदन को ही खत्म करने पर विचार कर रही है। दूसरी ओर, देश के चार बड़े राज्य ओडिशा, राजस्थान, असम और मध्यप्रदेश उच्च सदन स्थापित करने की कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राज्यों के लिए कितने सदन वाली व्यवस्था बेहतर है और इनकी मौजूदा दौर में कितनी प्रासंगिकता है।

यहां हैं उच्च सदन

संसद में लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही संविधान ने राज्यों को द्विसदनीय व्यवस्था का अधिकार दिया है। यद्यपि छह राज्यों में ही उच्च सदन की व्यवस्था है। इनमें आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की एक तिहाई से ज्यादा और चालीस से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा की तरह इसके सदस्य सीधे विधायकों या स्थायी निकायों द्वारा चुने जाते हैं अथवा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

पक्ष-विपक्ष के तर्क

उच्च सदन के पक्ष में रहने वालों का तर्क है कि इसके अस्तित्व में आने से बेहतर बहस हो सकेगी और बहुमत की सरकारों के जल्दबाजी में लिए निर्णयों को जांचा जा सकेगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि यह व्यवस्था मनोनीत पेशेवरों को विधान प्रकिया से जुड़ने की आज्ञा देती है। यद्यपि जो लोग दूसरे सदन के विरोध में हैं वो अक्सर तर्क देते हैं कि इससे कानून बनने में देरी होती है। इस सदन को राजनीतिक व्यक्तियों से भरा जाता है जो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। साथ ही यह सरकारी कोष की बर्बादी है।

संसद के पास अधिकार

संसद के पास राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्त करने का अधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित कर केंद्र को भेजती है। आंध्रप्रदेश में 1958 से उच्च सदन है, इसे 1985 में समाप्त कर दिया गया था। हालांकि इसे एक बार फिर 2007 में पुनर्गठित किया गया। राजस्थान और असम के विधान परिषद गठन के प्रस्ताव संसद में अटके हुए हैं।

स्थायी सदन है विधान परिषद

राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद स्थायी सदन है। इसके सदस्यों में से एक तिहाई हर दो साल की अवधि में कार्यमुक्त हो जाते हैं। यद्यपि विधानसभाओं को इनके सुझावों को न मानने का अधिकार होता है।

करोड़ों का बजट

ओडिशा ने प्रस्तावित उच्च सदन के लिए वार्षिक करीब 35 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने एकमुश्त 100 करोड़ रुपये और असम ने 19 करोड़ रुपये वार्षिक के साथ ही 69 करोड़ का खर्चा बताया है।

आंध्रप्रदेश की तीन राजधानियां

आंध्रप्रदेश विधानसभा ने तीन राजधानियां बनाने का प्रस्ताव किया है। दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर विशाखापत्तनम को कार्यकारी, अमरावती को विधायी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में प्रीटोरिया कार्यकारी, केपटाउन विधायी और ब्लोमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। वाइएसआर कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ एक बड़ी राजधानी बनाने का अर्थ दूसरे हिस्सों को नजरअंदाज करना है।

न्यूज गैलरी

आंध्र सरकार ने दिया विधान परिषद खत्म करने का संकेत

अमरावती : आंध्र प्रदेश के लिए तीन राजधानी बनाने से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर विधान परिषद में मात खाने के बाद राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि वह उच्च सदन को खत्म कर सकती है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्या ऐसा सदन होना चाहिए, जो केवल राजनीतिक मंशा के साथ काम करता है? उन्होंने कहा कि विधान परिषद होना कोई अनिवार्य नहीं है। यह हमारा ही बनाया हुआ है और केवल हमारी सुविधा के लिए है। इसलिए हमें सोमवार को आगे इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और फैसला लेना चाहिए कि विधान परिषद को जारी रखना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री बुधवार को विधान परिषद में जो कुछ हुआ, उस पर विधान सभा में चर्चा का जवाब दे रहे थे। (प्रेट्र)

राजद ने फिर लगाए पोस्टर, लिखा, ट्रबल इंजन की सरकार

पटना : बिहार में पोस्टर वार का सिलसिला जारी है। राजद की ओर से राजधानी में भाजपा एवं जदयू पर कटाक्ष करते हुए फिर पोस्टर लगाए गए हैं। राजद कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर बिहार को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया गया है। केंद्र और राज्य में भाजपा-जदयू गठबंधन की सरकार को डबल इंजन के बदले ट्रबल इंजन लिखा गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की भी तस्वीर लगाई गई है, जिसपर झूठ एक्सप्रेस और लूट एक्सप्रेस लिखा गया है। इससे पहले भी दोनों दलों की ओर से कई पोस्टर चिपकाए जा चुके हैं। दोनों ओर से एक दूसरे के शासनकाल की पोल खोलने वाले पोस्टरों में कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप हैं। (राब्यू)

राज ठाकरे ने बदला झंडा, बेटे को राजनीति में उतारा

बदले कलेवर ▶ 14 साल पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के गठन के समय बहुरंगी था पार्टी का झंडा

अब भगवा रंग पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर का चित्र होगा

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के मुखिया राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का झंडा बदलकर हिंदुत्व का रंग गाढ़ा करने का संकेत दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पुत्र अमित ठाकरे को भी राजनीति में उतार दिया है।

राज ठाकरे ने 14 साल पहले जब शिवसेना से अलग होकर मनसे का गठन किया तो अपने झंडे को बहुरंगी स्वरूप दिया था। उसमें नीला, हरा एवं भगवा रंग की पट्टियों पर चुनाव चिह्न रेल का इंजन शामिल किया था। लेकिन अब उनकी पार्टी के झंडे में भगवा रंग पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर का चित्र होगा। साथ ही नीचे कत्थई रंग की पट्टी पर पार्टी का नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लिखा होगा। यही नहीं, गुरुवार को पहली बार उनके मंच पर विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा भी नजर आई। इससे पहले उनके मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज की अर्धप्रतिमा के बगल में डॉ. भीमराव आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले एवं उनके दादा प्रबोधनकार ठाकरे की तस्वीरें हुआ करती थीं। माना जा रहा है कि राज ठाकरे ने अपनी रणनीति में यह परिवर्तन विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में आए बदलाव को देखते हुए किया है।

पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हिंदुत्व का झंडाबरदार समझी जानेवाली शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ सरकार बना ली है। इससे शिवसेना के कार्यकर्ता क्षुब्ध हैं। जिन दलों के खिलाफ वे पिछले 30 वर्षों से संघर्ष करते आए, आज उन्हीं दलों के साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे हैं। राज ठाकरे को लगता है कि इस स्थिति में वह यदि अपनी छवि हिंदुत्ववादी नेता की बनाते हैं, तो शिवसेना से छिटके कार्यकर्ता उनके साथ आ सकते हैं। सावरकर की प्रतिमा को मंच पर पहली बार स्थापित करना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस द्वारा सावरकर की लगातार आलोचना के बावजूद शिवसेना वैसी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर पा रही है, जैसी कि लोग उससे अपेक्षा करते हैं। 14 साल पहले मनसे की स्थापना के समय राज ठाकरे ने मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए ही अपने झंडे में हरे रंग की पट्टी को स्थान दिया था।

राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को भी पार्टी में शामिल कर राजनीति में आगे बढ़ाने का संकेत दे दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके चचेरे बड़े भाई उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे चुनाव लड़कर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता में राज अपने पुत्र अमित को पीछे नहीं रहने देना चाहते। कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य की राजनीति में किसी न किसी स्तर पर मनसे का तालमेल भाजपा के साथ हो सकता है। इसकी शुरुआत स्थानीय निकाय चुनावों से हो सकती है।

महाराष्ट्र नवनिर्वाण सेना(मनसे) के मुखिया राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे राजनीति के मैदान में कूद पड़े। मुंबई में गुरुवार को आयोजित समारोह के दौरान तलवार उठाए अमित। एएनआइ

महाराष्ट्र नवनिर्वाण सेना(मनसे) के मुखिया राज ठाकरे ने गुरुवार को पार्टी का नया झंडा लांच किया। एएनआइ

अल्पसंख्यक शिवसेना के खिलाफ नहीं : पवार

मुंबई, प्रेट्र : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कहा, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने उनसे कहा था कि अगर उनकी पार्टी शिवसेना से हाथ मिला ले तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा को सत्ता से बाहर रखा जाना चाहिए।

पिछले साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव शिवसेना और भाजपा साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बन पाने पर दोनों पार्टियां अलग हो गई थीं। राकांपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य में सरकार गठन को लेकर चले गतिरोध का जिक्र करते हुए पवार ने कहा कि तीन-चार हफ्तों तक (शिवसेना-भाजपा द्वारा) सरकार बनाने की दिशा में कोई कदम ही नहीं उठाया जा रहा था। इसके बाद शिवसेना के साथ संभावित गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों से सुझाव लिए गए। पवार ने कहा, 'अल्पसंख्यकों की ओर से हमें बताया गया कि अगर आप शिवसेना को साथ लेना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन भाजपा को दूर रखो।

अल्पसंख्यकों ने उस कदम (शिवसेना से बातचीत) का स्वागत किया था।' पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस घटनाक्रम ने देश को रास्ता दिखाया है और उन्होंने इस पहल के लिए समुदाय की सराहना की। उन्होंने दावा किया कि राज्य विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यकों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। जब समुदाय के सदस्य फैसला करते हैं तो किसी पार्टी की हार सुनिश्चित करते हैं। पवार ने कहा कि राकांपा ने जोर देकर राज्य सरकार में अल्पसंख्यक मामलों का विभाग मांगा था ताकि समुदाय के लिए कल्याणकारी कार्य किए जा सकें। मालूम हो कि राकांपा नेता नवाब मलिक राज्य में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं।

शरद पवार। फाइल

मुंबई के 'उत्तर प्रदेश दिवस' में शामिल होंगे उप्र के कई हैवीवेट नेता

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई : मुंबई में शुक्रवार को मनाए जाने वाले 'उत्तर प्रदेश दिवस समारोह' में इस बार यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस एवं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल आदि उपस्थित रहेंगे। पिछली बार इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया था।

उत्तर प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश दिवस' दो वर्ष पहले मनाना शुरू किया गया, लेकिन मुंबई में उत्तर प्रदेश मूल के लोग पिछले 32 वर्षों से उत्तर प्रदेश दिवस धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। यह न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान प्रदर्शित करने वाला समारोह बन चुका है, बल्कि चुनावी वर्षों में शक्ति प्रदर्शन का माध्यम भी बन जाता है। इस समारोह के जरिये नेता मुंबई की आबादी में करीब 40 फीसद हिंदी भाषियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का मौका नहीं छोड़ते।

अभियान के संयोजक मुंबई भाजपा के महासचिव अमरजीत मिश्र ने बताया कि आजादी मिलने के बाद तक उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रॉविंस आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाता था। यह नाम लंबा था, इसलिए संक्षेप में इसे यूनाइटेड प्रॉविंस या यूपी ही कहा जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसके संक्षिप्त नाम 'यूपी' से प्रेम था, इसलिए इसका नाम बदलते समय भी यूपी शब्द को बरकार रखा और इस प्रदेश का नया नामकरण उत्तर प्रदेश (यूपी) हुआ। नए नाम का गजट 24 जनवरी, 1950 को जारी हुआ, इसलिए अभियान संस्था इसी तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाती है। मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की शुरुआत हमेशा महाराष्ट्र गीत 'जय जय महाराष्ट्र माझा' से होती है। उत्तर प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश दिवस' के आयोजन का श्रेय वहां के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को जाता है।

जेल से निकलते ही 2017 के मामले में गिरफ्तार हुए हार्दिक पटेल

अहमदाबाद, प्रेट्र : कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल गुरुवार को जैसे ही साबरमती सेंट्रल जेल से बाहर निकले, गांधीनगर जिले की पुलिस ने 2017 के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले कांग्रेस नेता को देशद्रोह के मामले में कोर्ट से जमानत मिली थी। 2015 के मामले में सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने के कारण हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया था।

हार्दिक पटेल। फाइल

अहमदाबाद में एक स्थानीय कोर्ट ने बुधवार को गिरफ्तारी के चार दिनों बाद जमानत दे दी। गुरुवार को जेल से बाहर आते ही गांधीनगर जिले की मनसा तहसील पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी 2017 में दर्ज एक एफआइआर के सिलसिले में की गई है। पुलिस से अनुमति लिए बगैर सभा को संबोधित करने के आरोप में एफआइआर दर्ज की गई थी। मनसा के इंस्पेक्टर एसएस पवार ने कहा कि एफआइआर तो तब दर्ज की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी आज की गई है।

आजम के जौहर विवि पर कार्रवाई 26 किसानों को मिला कब्जा

जागरण संवाददाता, रामपुर

सपा सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने गुरुवार को भी बड़ी कार्रवाई की। 26 किसानों को यूनिवर्सिटी में शामिल की गई जमीन पर कब्जा दिला दिया गया।

एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी गुरुवार दोपहर राजस्व टीम के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचे और पैमाइश कराकर किसानों को कब्जा दिलाया। पैमाइश की प्रकिया शाम तक चली। इस दौरान लेखपालों के साथ किसान भी मौजूद रहे। इन किसानों ने जमीन पर कब्जा करने के आरोप में आजम पर मुकदमे कराए थे। एसडीएम ने बताया कि इन किसानों की करीब 20 बीघा जमीन है, जो बिना रजिस्ट्री के जबरन यूनिवर्सिटी के अंदर कर ली गई थी। सभी किसानों को उनकी जमीन पर कब्जा दिला दिया गया है।

तब भूमाफिया घोषित हुए थे आजम : एसडीएम तिवारी ने बताया कि आलियागंज के 26 किसानों ने जुलाई 2019 में जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह को शपथ पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम ने सपा शासनकाल में उनकी जमीन जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली। विरोध करने पर तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां ने उन्हें डराया धमकाया और हवालात में बंद किया। इन शपथ पत्रों की जांच कराने के बाद 12 जुलाई 2019 को प्रशासन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद आलियागंज के उन सभी 26 किसानों ने अजीमनगर थाने में अलग-अलग तहरीर देकर रिपोर्ट कराई। 18 जुलाई को एसडीएम की ओर से आजम का नाम एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया। इस पर उन्हीं लोगों के नाम दर्ज कराए जाते हैं, जो जमीन पर कब्जा करते हैं।

सरकार ने भी लिया है 104 बीघा जमीन पर कब्जा : प्रशासन ने बुधवार को भी यूनिवर्सिटी की 104 बीघा जमीन को कब्जे में ले लिया था। जमीन 10 अनुसूचित जातियों से डीएम की अनुमति लिए बिना खरीदी गई थी। नियमानुसार अनुसूचित जातियों की जमीन खरीदने के लिए डीएम की अनुमति जरूरी है।

आजम खां। फाइल

'महाराष्ट्र सरकार के विज्ञापनों में पीएम का फोटो अवश्य लगे'

मुंबई, प्रेट्र : वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार के सभी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

गुरुवार को लिखे इस पत्र में फड़नवीस ने कहा है कि राज्य सरकार के विज्ञापनों में प्रधानमंत्री के फोटो नहीं लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 13 मई, 2015 और 18 मार्च, 2016 के आदेश में सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री का फोटो प्रकाशित करने के बारे में उल्लेख किया था। शीर्ष अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने भी 11 अगस्त, 2017 को सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो लगाने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया था।

फड़नवीस का कहना है कि 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना' से जुड़े विज्ञापनों में इस सर्कुलर का उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री का फोटो लगाया गया है जबकि यह योजना पूरी तरह केंद्र पोषित है।

नीतीश कुमार की पवन को दो टूक- जहां जाना हैं जाएं, मेरी शुभकामनाएं साथ हैं

राज्य ब्यूरो, पटना

जदयू के पूर्व राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा को जदयू ने नमस्कार कर लिया है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) पर लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रहे पवन वर्मा पर नीतीश कुमार ने दो टूक अंदाज में गुरुवार को कहा कि उन्हें जहां जाना हैं जाएं, मेरी शुभकामना है उन्हें। पवन वर्मा लगातार सीएए और एनआरसी के मसले पर जिस तरह से जदयू पर हमलावर थे उससे जदयू के भीतर इस मसले पर द्वंद्व की बात कही जा रही थी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पवन वर्मा को नसीहत देते हुए साफ कर दिया कि जदयू के भीतर सीएए पर किसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं। पार्टी के किसी नेता का कोई वक्तव्य दल का आधिकारिक वक्तव्य नहीं हो सकता।

सुभाषचंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गांधी मैदान के समीप सुभाष प्रतिमा स्थल परिसर पहुंचे मुख्यमंत्री ने काफी तल्ख अंदाज में पवन वर्मा पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर उनके मन में कुछ था तो आकर विमर्श करना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि आप इस तरह का वक्तव्य दे रहे कि हमसे क्या बात होती थी। अब हम कहेंगे क्या कि हमसे उनकी क्या-क्या बात हो होती थी? यह कोई तरीका है क्या? इसके बाद भी मेरे मन में उनके प्रति इज्जत है।

आइएफएस से राजनीति का सफर : जदयू के महासचिव रह चुके पवन वर्मा भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) के पूर्व अधिकारी रहे हैं। 2013 में सेवानिवृत्त हुए। नीतीश कुमार के सलाहकार भी रह चुके वर्मा अब तक कई किताबें लिख चुके हैं, जिनमें से कुछ बेहद चर्चित रही हैं। लंदन में नेहरू सेंटर में प्रतिष्ठित वार्षिक नेहरू मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया। वह गालिब मेमोरियल ट्रस्ट के संयोजक भी हैं। कूटनीति, साहित्य, संस्कृति और सौंदर्यशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए पवन को 2005 में इंडियानापोलिस विश्वविद्यालय डॉक्टरेट की मानद उपाधि दे चुका है। दिसंबर 2012 में भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, (ड्रक ठुक्से) से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। 2006 में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ, कोलकाता) उन्हें सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड से प्रदान कर चुका है।

संभाल चुके हैं कई पद : 2001 से 2004 तक साइप्रस में भारतीय उच्चायुक्त रहे। 2005 से 2009 तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक भी रहे। 2009 से 2013 तक भूटान में भारत के राजदूत रहे। 2014 से 2016 तक बिहार से राज्यसभा सदस्य रहे।

नीतीश कुमार और पवन वर्मा की फाइल फोटो।

जदयू में दो तरह के लोग हैं। एक जो मेहनत कर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। दूसरे अनुकंपा वाले हैं। पार्टी में पद पाते हैं, अनाप-शनाप बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों के रहने न रहने से पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता है।

-आरसीपी सिंह, सांसद और राष्ट्रीय महासचिव, जदयू

बदला रुख

राहुल की हार के बाद था पहला दौरा, टीस न छिपा सका मां का दिल, न कहीं ठहराव और न अभिवादन, सिर्फ गमगीन परिवारों से मुलाकात कर लौटीं

रूठी अमेठी में सोनिया गांधी भी नजर आई अनमनी सी

जितेंद्र शर्मा, रायबरेली

कारवां गुजर गया और अमेठी के बाशिंदे गुबार देखते रह गए। गुबार दिखा रहा था कि राजनीतिक रिश्तों की डोर कितनी कमजोर होती है। पिछले कई दशकों से नेहरू-गांधी परिवार का जो मजबूत रिश्ता इस धरती से बना, वह राहुल गांधी की एक हार से यूं बिखर गया, जिसे सहेजने की तड़प न बतौर पार्टी अध्यक्ष मां सोनिया गांधी में दिखी और न ही महासचिव बहन प्रियंका वाड्रा में। पिछले दिनों हादसे में मारे गए ग्रामीणों के परिजनों से मुलाकात को छोड़ दें तो रूठी अमेठी में सोनिया अनमनी सी ही नजर आईं।

सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा बुधवार को रायबरेली पहुंचीं और भुएमऊ गेस्ट हाउस में प्रदेशभर से प्रशिक्षण के लिए जुटे जिला और शहर अध्यक्षों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। गुरुवार दोपहर करीब 12.30 बजे दोनों कांग्रेस नेता अमेठी के लिए रवाना हो गईं। सड़क के दोनों किनारों पर क्षेत्रवासी इस उम्मीद में खड़े थे कि शायद सोनिया या प्रियंका हालचाल लें, मगर ऐसा नहीं हुआ। गाड़ियां सीधे भरेथा मौजा में रुकीं, जहां के छह ग्रामीणों की पिछले दिनों सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। दो परिवारों से कुछ मिनटों की मुलाकात कर काफिला फिर उसी रफ्तार से वापस फुरसतगंज हवाई पट्टी के लिए दौड़ पड़ा। अमेठी के बाशिंदों को शायद इसकी उम्मीद न रही होगी, क्योंकि राहुल गांधी यहां से सांसद रहे, तब सोनिया आती थीं तो भीड़ देखकर गाड़ी रुकवा देती थीं। चलते-चलते हालचाल ले लेती थीं। न रुकीं तो गाड़ी का शीशा नीचे कर हाथ जोड़ लेती थीं। राहुल गांधी की हार के बाद सोनिया का यह पहला अमेठी दौरा था। प्रियंका भी उसके बाद एक ही बार कुछ देर के लिए आई थीं।

अमेठी के भरेथा गांव में सड़क हादसे में मृतक कल्पनाथ कश्यप के आवास पर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करतीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा। हृदेश चंदेल

संघर्ष की बेला है, घर और मजबूत करें : सोनिया

जासं रायबरेली : बुधवार की शाम लगभग साढ़े पांच बजे भुएमऊ गेस्टहाउस पहुंची कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा लगभग 19 घंटे तक रायबरेली में रहीं लेकिन प्रशिक्षण के संयुक्त सत्र में बोलने का मोर्चा प्रियंका ने ही संभाला। सोनिया ने सिर्फ तीन से पांच मिनट में ही अपनी बात रखी। उन्होंने लोगों से कहा कि ये हमारा घर है। घर के लोगों को संघर्ष के लिए और मजबूत होना चाहिए। आप लोग अपने को मजबूत करें, क्योंकि 2022 की लड़ाई लड़नी है।

गुजरात भाजपा के दो और विधायक नाराज, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (जीएनएफसी) लिमिटेड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा के दो विधायकों ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पत्र लिखा है। इससे राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है।

सीएम रूपाणी के कार्यकाल के दौरान यह पहला मौका है, जब पार्टी नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर असंतोष जाहिर किया है। वडोदरा के सावली से विधायक केतन इनामदार ने गत दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनामदार के समर्थन में सावली नगरपालिका के 16 पार्षद तथा 300 भाजपा नेता व पदाधिकारी भी इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतूभाई वघाणी का दावा है कि इनामदार को मना लिया गया है। इस बीच भरूच जिले के दो विधायकों दुष्यंत पटेल व अरुण सिंह राणा ने जीएनएफसी में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम रूपाणी को पत्र लिखा है। उनका पत्र गुरुवार को मीडिया में आया। आरोप है कि वागरा में जीएनएफसी के टीडीआइ प्लांट में 7,700 मीट्रिक टन केमिकल्स जमा किया गया, जिसे खतरनाक गैस फॉस्जीन से बनाया गया है। इसी गैस से भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसा हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावडा ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि दो और भाजपा विधायक इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने इनामदार को पार्टी में शामिल होने के लिए खुला ऑफर देते हुए कहा, 'आधी पिच पर आकर खेलने वाले रूपाणी को उनके विधायक ही स्टंप आउट करेंगे।' सीएम रूपाणी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ज्यादा खुश न हो। कई कांग्रेसी विधायक भाजपा में आने के लिए लाइन में लगे हैं।